2016 का विधेयक संख्यांक 210

[दि ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016

उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने तथा उनसे संबद्ध तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2016 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "समुचित सरकार" से,–

(i) केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार ;

(ii) राज्य सरकार या उस सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन के संबंध में राज्य सरकार,

अभिप्रेत है ;

(ख) "स्थापन" से,–

(i) किसी केंद्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निकाय या प्राधिकरण या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी और इसके अंतर्गत कोई सरकारी विभाग भी है ; या 2013 का 18

(ii) कोई कंपनी या निगमित निकाय या संगम या व्यष्टिकों का निकाय, फर्म, सहकारी या अन्य सोसाइटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संस्था,

अभिप्रेत है ;

(ग) "समाविष्ट शिक्षा" से शिक्षा की कोई प्रणाली अभिप्रेत है, जिसमें अन्य विद्यार्थियों के साथ उभयलिंगी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं और अध्यापन और शिक्षण की प्रणाली ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित रूप से अंगीकृत की गई है ;

(घ) "संस्था" से उभयलिंगी व्यक्तियों को स्वीकार करने, उनकी देखरेख, संरक्षण करने, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास या किसी अन्य सेवा के लिए कोई संस्था, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अभिप्रेत है ;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकरण" से अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के संबंध में यथास्थिति, नगरपालिक सेवाएं या मूल सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित, नगर निगम या नगरपालिका या पंचायत या कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है ;

(च) "राष्ट्रीय परिषद्" से धारा 17 के अधीन स्थापित उभयलिंगी व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद् अभिप्रेत है ;

(छ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा बनाए गए

नियम अभिप्रेत हैं ;

(झ) "उभयलिंगी व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(अ) न तो पूर्णतया स्त्री है न ही पूर्णतया पुरुष है ; या

(आ) स्त्री या पुरुष दोनों का संयोजन है ; या

(इ) न तो स्त्री है न ही पुरुष है ; और

जिसकी लिंग की अनुभूति जन्म के समय उस व्यक्ति को समनुदेशित लिंग से मेल नहीं खाती है और इसके अंतर्गत अंत:लैंगिक भिन्नताएं और लिंग विलक्षणताओं सहित परा-नर और परा-नारी व्यक्ति भी हैं ।

अध्याय 2

कतिपय कृत्यों का प्रतिषेध

विभेद का प्रतिषेध ।

3. कोई व्यक्ति किसी उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित आधारों पर विभेद नहीं करेगा, अर्थात् :–

(क) शैक्षिक संस्थापनों और उनकी सेवाओं का प्रत्याख्यान या उन्हें जारी न रखना या अनुचित व्यवहार ;

(ख) नियोजन या उपजीविका के संबंध में अनुचित व्यवहार ;

(ग) नियोजन या उपजीविका का प्रत्याख्यान या समाप्ति ;

(घ) स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं का प्रत्याख्यान या उन्हें जारी न रखना या अनुचित व्यवहार ;

(ङ) साधारण पब्लिक या पब्लिक को रूढ़िजन्य रूप से उपलब्ध समर्पित किन्हीं मालों, वास-सुविधा, सेवा, सुविधा, फायदा, विशेषाधिकार या अवसर तक पहुंच या उपबंध या अधिभोग का प्रत्याख्यान या उन्हें जारी न रखना ;

(च) संचलन के अधिकार का प्रत्याख्यान या उसे जारी न रखना या उसके संबंध में अनुचित व्यवहार ;

(छ) निवास करने, क्रय करने, भाटक पर लेने या अन्यथा किसी संपत्ति को अधिभोग में लेने के संबंध में अधिकार का प्रत्याख्यान या उसे जारी न रखना या अनुचित व्यवहार ;

(ज) पब्लिक या प्राइवेट पद के लिए खड़े होने या उसे धारण करने के लिए अवसर का प्रत्याख्यान या जारी न रखना या अनुचित व्यवहार ;

(झ) सरकारी या प्राइवेट स्थापनों, जिनकी देखरेख या अभिरक्षा में कोई उभयलिंगी व्यक्ति है, में पहुंच का प्रत्याख्यान या उनसे हटाना या उनमें अनुचित व्यवहार करना ।

अध्याय 3

उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान को मान्यता

उभयलिंगी व्यक्ति की पहचान को मान्यता ।

4. (1) उभयलिंगी व्यक्ति को उस रूप में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उभयलिंगी के रूप में मान्यताप्राप्त व्यक्ति को स्वयं-अनुभव की गई लिंग पहचान का अधिकार होगा ।

पहचान के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन ।

5. उभयलिंगी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को, उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे दस्तावेजों, जो विहित किए जाएं, के साथ आवेदन कर सकेगा :

परंतु अप्राप्तवय बालक की दशा में ऐसा आवेदन ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक द्वारा किया जाएगा ।

जिला छानबीन समिति ।

6. (1) जिला मजिस्ट्रेट, धारा 5 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसे आवेदन को उभयलिंगी व्यक्तियों को मान्यता देने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा गठित जिला छानबीन समिति को निर्दिष्ट करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जिला छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,–

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी ;

(ख) जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी ;

(ग) मनोविज्ञानी या मनोचिकित्सक ;

(घ) उभयलिंगी समुदाय का एक प्रतिनिधि ; और

(ङ) समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उस सरकार का एक अधिकारी ।

पहचान का प्रमाणपत्र जारी करना ।

7. (1) जिला मजिस्ट्रेट आवेदक को जिला छानबीन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उभयलिंगी व्यक्ति को धारा 5 के अधीन पहचान का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, ऐसे व्यक्ति के लिंग को उभयलिंगी के रूप में उपदर्शित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(2) उभयलिंगी व्यक्ति का लिंग सभी शासकीय दस्तावेजों में उपधारा (1) के अधीन जारी प्रमाणपत्र के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी प्रमाणपत्र अधिकार प्रदत्त करेगा और उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान की मान्यता का सबूत होगा ।

लिंग में परिवर्तन ।

8. (1) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् यदि उभयलिंगी व्यक्ति के लिंग में कोई परिवर्तन होता है तो वह पुनरीक्षित प्रमाणपत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर और जिला छानबीन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर लिंग में परिवर्तन को उपदर्शित करते हुए ऐसे प्ररूप और रीति तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) वह व्यक्ति, जिसे पुनरीक्षित प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जन्म प्रमाणपत्र और ऐसे व्यक्ति की पहचान से संबंधित सभी अन्य शासकीय दस्तावेजों में अपने प्रथम नाम में परिवर्तन करने का हकदार होगा :

परंतु लिंग में ऐसा परिवर्तन और उपधारा (1) के अधीन जारी पुनरीक्षित प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हकदारियों को प्रभावित नहीं करेगा ।

अध्याय 4

सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय

समुचित सरकार की बाध्यता ।

9. (1) समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा समाज में उन्हें समाविष्ट करने के लिए कदम उठाएगी ।

(2) समुचित सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों और हितों को संरक्षित करने के लिए तथा सरकार द्वारा विरचित कल्याणकारी स्कीमों में उनकी पहुंच को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हों ।

(3) समुचित सरकार कल्याणकारी स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करेगी जो उभयलिंगी संवेदी, लांछन न लगाने वाले तथा गैर-विभेदकारी होंगे ।

(4) समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के उद्धार, संरक्षण और पर्यावास तथा ऐसे व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाएगी ।

(5) समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों द्वारा सांस्कृतिक और मनोरंजन क्रियाकलापों में भाग लेने के अधिकार का संवर्धन और संरक्षण करने के लिए समुचित उपाय करेगी ।

अध्याय 5

स्थापनों और अन्य व्यक्ति की बाध्यता

नियोजन में विभेद न होना ।

10. कोई स्थापन नियोजन, जिसके अंतर्गत भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दे हैं किंतु उस तक ही सीमित नहीं है, के संबंध में किसी उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विभेद नहीं करेगा ।

स्थापनों की बाध्यता ।

11. प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा और उभयलिंगी व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जो विहित की जाएं ।

शिकायत निवारण तंत्र ।

12. प्रत्येक स्थापन, जो एक सौ या उससे अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना है, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा ।

निवास का अधिकार ।

13. (1) किसी उभयलिंगी व्यक्ति को उसके माता-पिता से या उसके निकट कुटुंब से उसके उभयलिंगी होने के आधार पर सिवाय, ऐसे व्यक्ति के हित में सक्षम न्यायालय के आदेश के, पृथक् नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक उभयलिंगी व्यक्ति को,–

(क) उस गृहस्थी में जहां उसके माता-पिता या निकट कुटुंब के सदस्य निवास करते हैं, निवास का अधिकार होगा ;

(ख) ऐसे गृहस्थी या उसके किसी भाग से अपवर्जित न करने का अधिकार होगा ;

(ग) ऐसी गृहस्थी की सुविधाओं का गैर-विभेदकारी रीति में उपभोग करने का अधिकार होगा ।

(3) जहां किसी उभयलिंगी के माता-पिता या उसके निकट कुटुंब का सदस्य उसकी देखभाल करने में असमर्थ है, वहां सक्षम न्यायालय आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र में रखे जाने का निदेश देगा ।

अध्याय 6

उभयलिंगी व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

शैक्षिक संस्थाओं की उभयलिंगी व्यक्तियों को समाविष्ट शिक्षा प्रदान करने की बाध्यता ।

14. समुचित सरकार द्वारा वित्तपोषित या मान्यताप्राप्त सभी शैक्षिक संस्थाएं समाविष्ट शिक्षा और क्रीड़ा, मनोरंजन और अवकाश कार्यकलापों के लिए बिना किसी विभेद के अन्य के साथ समानता के आधार पर अवसर उपलब्ध कराएंगी ।

वृत्तिक प्रशिक्षण और स्व-रोजगार ।

15. समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों की जीविकोपार्जन को सुकर बनाने और सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत वृत्तिक प्रशिक्षण तथा स्व-रोजगार भी है, कल्याणकारी स्कीमें तथा कार्यक्रम तैयार करेगी ।

स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं ।

16. समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :–

(क) पृथक् ह्यूमन इम्युनो डेफिसेंसी वायरस सीरो-सर्विलेंस केंद्र ;

(ख) चिकित्सा देखरेख सुविधा, जिसके अंतर्गत लिंग पुन: समनुदेशन शल्यक्रिया और हार्मोन संबंधी उपचार भी है, प्रदान करना ;

(ग) पूर्व और पश्च लिंग समनुदेशन शल्यक्रिया और हार्मोन चिकित्सा परामर्श ;

(घ) वर्ल्ड प्रोफेसन एसोसिएशन फार ट्रांसजेंडर हेल्थ गाइडलाइंस के अनुसार लिंग समनुदेशन शल्यक्रिया से संबंधित चिकित्सा मैनुअल निकालना ;

(ङ) उनके विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान देने के लिए चिकित्सकों के चिकित्सा पाठ्यचर्या और अनुसंधान का पुनर्विलोकन करना ;

(च) अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं तथा केंद्रों में उभयलिंगी व्यक्तियों तक पहुंच को सुकर बनाना ;

(छ) उभयलिंगी व्यक्तियों के समग्र बीमा योजना द्वारा चिकित्सा व्यय को चुकाने के लिए उपबंध ।

अध्याय 7

उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद्

उभयलिंगी राष्ट्रीय परिषद् ।

17. (1) केंद्रीय सरकार उसे इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने और सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक उभयलिंगी राष्ट्रीय परिषद् का गठन करेगी ।

(2) परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,–

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभारी संघ का मंत्री, अध्यक्ष पदेन ;

(ख) सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभारी राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष पदेन ;

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभारी भारत सरकार का सचिव, सदस्य पदेन ;

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा विधि कार्य विभाग, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग तथा नीति आयोग प्रत्येक से भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक प्रतिनिधि, सदस्य पदेन ;

(ङ) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक में से भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक प्रतिनिधि, सदस्य पदेन ;

(च) चक्रानुक्रम में राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्येक का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि, सदस्य पदेन ;

(छ) उभयलिंगी समुदाय के पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों से चक्रानुक्रम द्वारा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से प्रत्येक से एक, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, सदस्य ;

(ज) उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच सदस्य ;

(झ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण से व्यौहार करने वाला भारत सरकार का संयुक्त सचिव, सदस्य-सचिव

पदेन ।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न राष्ट्रीय परिषद् का सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

परिषद् के कृत्य ।

18. राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित कृत्यों को करेगी, अर्थात् :–

(क) केंद्रीय सरकार को उभयलिंगी व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाएं तैयार करने पर परामर्श देना ;

(ख) उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए समानता और पूर्ण सहभागिता हासिल करने के लिए डिजाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों के समाघात की मानीटरी तथा मूल्यांकन करना ;

(ग) सरकार के विभागों तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, जो उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित मामलों से व्यौहार कर रहे हैं, के कार्यकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वय करना ;

(घ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

अपराध और शास्तियां ।

19. जो भी,–

(क) किसी उभयलिंगी व्यक्ति को, सिवाय सरकार द्वारा लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा के, भिक्षावृत्ति करने या बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी के ऐसे ही रूपों में कार्य करने के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा ;

(ख) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक स्थान में आवागमन के अधिकार का प्रत्याख्यान करेगा या ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, जिस तक अन्य व्यक्तियों की पहुंच है या अधिकार है, के उपयोग या उस तक पहुंच को अवरुद्ध करेगा ;

(ग) उभयलिंगी व्यक्ति को गृहस्थी, ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए विवश करेगा या छोड़ना कारित करेगा ;

(घ) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या भलाई की अपहानि करेगा या क्षति करेगा या खतरे में डालेगा, चाहे मानसिक या शारीरिक हो या ऐसे कृत्य करेगा जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग कारित करना, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग भी है,

कारावास से जो छह मास से कम नहीं होगा, किंतु दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

20. केंद्रीय सरकार समय-समय पर संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् परिषद् को ऐसी राशियों का प्रत्यय कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे ।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना ।

21. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

22. इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

23. (1) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 5 के अधीन कोई आवेदन किया जाएगा ;

(ख) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पहचान प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ;

(ग) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जाएगा ;

(घ) धारा 10 के अधीन उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं ;

(ङ) धारा 18 के अधीन राष्ट्रीय परिषद् के अन्य कृत्य ;

(च) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निप्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं

पड़ेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बना है उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा या निदेशों द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उभयलिंगी समुदाय देश में एक ऐसा समुदाय है जो सर्वाधिक हाशिये पर है क्योंकि वे 'पुरुष' या 'स्त्री' के लिंग के सामान्य प्रवर्गों में फिट नहीं होते हैं । परिणामस्वरूप, उन्हें सामाजिक बहिष्कार से भेदभाव, शैक्षिक सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

2. तथापि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 15 का खंड (1) और खंड (2) तथा अनुच्छेद 16 का खंड (2), अन्य बातों के साथ, अभिव्यक्त निबंधनों में लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध और अनुच्छेद 19 का खंड (1) और उपखंड (क) सभी नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य को सुनिशचित करता है, फिर भी उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद और अत्याचार का होना जारी है ।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में 15 अप्रैल, 2014 को पारित अपने आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को उभयलिंगी समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाने का और संविधान के भाग 3 के अधीन और संसद् तथा राज्य विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई अन्य विधियों के अधीन उनके अधिकारों के सुरक्षापायों के प्रयोजन के लिए उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मानने का निदेश दिया है ।

4. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016 निम्नलिखित के लिए है—

(क) उभयलिंगी व्यक्ति को परिभाषित करने ;

(ख) उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करने;

(ग) उभयलिंगी व्यक्ति को उस रूप में मान्यता देने के लिए उसे अधिकार प्रदत्त करने और स्वत: अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करने ;

(घ) उभयलिंगी व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने ;

(ङ) यह उपबंध करने कि कोई स्थापन नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित विषयों में किसी उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा ;

(च) प्रत्येक स्थापन में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने ;

(छ) राष्ट्रीय उभयलिंगी परिषद् की स्थापना करने ;

(ज) विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए दंड देने ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
27 जुलाई, 2016

थावरचंद गहलौत

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 9 का उपखंड (2) यह कथन करता है कि समुचित सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों और उस सरकार द्वारा विरचित कल्याण स्कीमों तक इनकी पहुंच को सुकर बनाएं ।

2. विधेयक के खंड 9 का उपखंड (3) यह कथन करता है कि समुचित सरकार ऐसी कल्याण स्कीमों और कार्यक्रमों की विरचना करेगी, जो उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए संवेदनशील, निष्कलंककारी और अविभेदकारी हों ।

3. विधेयक का खंड 15 यह कथन करता है कि समुचित सरकार ऐसी कल्याण स्कीमों और कार्यक्रमों की विरचना करेगी, जो उभयलिंगी व्यक्तियों की आजीविका को सुकर बनाएं और उसके लिए समर्थकारी हों, इनके अंतर्गत उनका व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्व:नियोजन भी है ।

4. विधेयक के खंड 16(1)(छ) में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एक व्यापक बीमा स्कीम द्वारा उनके चिकित्सीय व्ययों को उसमें सम्मिलित करने हेतु उपबंध अंतर्विष्ट हैं ।

5. विधेयक का खंड 17 उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् के गठन का प्रस्ताव करता है ।

6. विधेयक का खंड 20 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार समय-समय पर, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् परिषद् को ऐसी राशियां प्रदत्त करेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

7. चालू वित्तीय वर्ष के लिए, उभयलिंगी व्यक्तियों संबंधी स्कीम के लिए 15 करोड़ रुपए की रकम बजट संबंधी व्यय के रूप में आबंटित की गई है । इस प्रक्रम पर यह संभव नहीं है कि उस समय उपगत होने वाले संभावित संपूर्ण वित्तीय बोझ को प्राक्कलित किया जा सके, यदि प्रस्तावित विधान के सभी उपबंधों को क्रियान्वित किया जाता है, यदि वे अधिनियमित हो जाते हैं । उपरोक्त व्यय की पूर्ति उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए योजना स्कीम के बजट संबंधी आबंटन से की जाएगी ।

8. विधेयक में कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 23 समुचित सरकार को विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे– (क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 5 के अधीन कोई आवेदन किया जाएगा ; (ख) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पहचान प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ; (ग) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाएगा ; (घ) धारा 10 के अधीन उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं ; (ङ) धारा 18 के खंड (घ) के अधीन राष्ट्रीय परिषद् के अन्य कृत्य ; (च) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए, हैं ।

वे विषय, जिनके संबंध में पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND—1990LS(CRC)—29-7-2016.

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	1	नियम अभिप्रेत	नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत
3	8	सहित परा-नर और परा-नारी व्यक्ति	सहित उभय-नर और उभय-नारी व्यक्ति
3	13	संस्थापनों	स्थापनों